Probe in Scrap Deal

586. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the Pioneer, dated 3rd September, 1997 under the heading "Centre may ask CBI to probe PSU Scrap deal";

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the case relating to the sale of scrap by the MSTC Ltd. to private firm has been referred to CBI; and

(d) the action taken by Government against the official concerned for awarding the sale to the private firm?

THE MINISTER OF STEEL AND THE MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) and (b) Yes, Sir, However, the press report is not wholly correct.

M/s. Sujana Steels Ltd., Hyderabad (and not Surana Steel as mentioned in the Press Report) had approached MSTC during early 1996 for purchase of 20,000 tonnes of shredded scrap from its Madras stockyard at the then ruling prices. The MSTC Board considered the request and decided (and not the then CMD, MSTC as alleged in the news report) to seel the stocks to the above firm under a tripartite agreement between M/s. MSTC Ltd., Sujana Steels Ltd. and SJK Steel Corporation Ltd. under the post-dated cheque facility scheme of the Company. Prior to this, MSTC had proposed to invest Rs. 15 crores in the equity of M/s. SJK Steel Corporation Ltd, of which M/s. Sujana Steels Ltd. was a joint co-promoter. According to the tripartite agreement Rs. 15 crores were to be adjusted against MSTC's equity participation in the above joint venture proposal subject to Government approval within a period of six months. In the absence of Government approval for the said joint venture proposals, the amount became due for payment but the post dated cheques furnished by M/s. Sujana Steels Ltd. bounced. In view of this, MSTC Ltd. has initiated legal proceedings against M/s. Sujana Steels Ltd. for recovery of the amount.

(c) The Ministry of Steel has not referred the matter relating to sale of scrap by MSTC through the private firm to CBI.

(d) Question does not arise in view of (a) & (b) above.

Failure of Sale Target of SAIL

587. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the sale target of Steel Authority of India Limited has failed in the recent months; if so, the reasons of failure;

(b) whether the cheap import of steel is influencing the SAIL's market; and

(c) if so, the steps being taken to avoid this problem?

THE MINISTER OF STEEL AND THE MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) The total sales of pig iron and mild steel during the current financial year, upto October, 1997, have registered a growth over that of the corresponding period last year.

(b) and (c) Yes, Sir. Cheap import of steel is influencing the Indian steel producers' market including that of SAIL. Steps have been initiated for levying anti-dumping duty on such steel materials.

निजी क्षेत्र में इस्पात इकाइयाँ

588. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई इस्पात इकाइयों का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त किसी इकाई में कोई विदेशी निवेश किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस्पात की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र और 177 विद्युत चाप भट्टी आधारित लघु इस्पात संयंत्र स्थापित हैं जिनका ब्यौरा नीचे विवरण में दिया गया है। इन संयंत्रों के अतिरिक्त बहुत से प्रेरण भट्टी आधारित लघु इस्पात संयंत्र हैं जो अधिकांशतः लघु क्षेत्र में हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने मैसर्स मार्टेक लि०, यू०के० द्वारा जमशेदपुर, बिहार में स्थित मौजूदा विद्युत चाप भट्टी आधारित इस्पात संयंत्र मैसर्स उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.457 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमोदित कर दिया है।

(घ) और (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि गुणवत्ता विशेष तौर से उदारीकरण के बाद के परिदृश्य में सदैव महत्वपूर्ण है और इस्पात का उत्पादन करने वाली कंपनी को अपने आपको प्रति स्पर्धात्मक बनाने के लिए इस पहलू के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा।

विवरण

विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की संख्या

क्र० सं०	राज्य	इकाइयों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7
2.	आसाम	2
3.	बिहार	7
4.	चण्डीगढ़	1
5.	दिल्ली	2
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	7
8.	हरियाणा	12
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	जम्मू और कश्मीर	2
11.	कर्नाटक	11
12.	मध्य प्रदेश	15
13.	महाराष्ट्र	32
14.	उड़ीसा	1
15.	पाण्डिचेरी	3
16.	पंजाब	9
17.	राजस्थान	7
18.	तमिलनाडु	5
19.	उत्तर प्रदेश	27
20.	पश्चिम बंगाल	23
		178

वसंत विहार में पानी की कम आपूर्ति

589. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी०पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी, वसंत विहार, नई दिल्ली के ब्लाक 71 तथा ब्लाक 72 के निवासियों को दूसरे ब्लाक के निवासियों की तुलना में पानी की बहुत कम मात्रा मिल रही है;

(ख) क्या उक्त ब्लाकों में रहने वाले कर्मचारियों को प्रतिदिन सुबह 30 मिनट के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है;

(ग) क्या उक्त समस्या की ओर सी०पी०डब्ल्यू०डी० के किसी भी अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त ब्लाकों के निवासियों को पानी की उचित मात्रा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन): (क) से (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि सी पी डब्ल्यू डी कालोनी के 71 एवं 72 ब्लाकों सहित वसन्त विहार के सभी ब्लाकों को पानी का उचित वितरण किया जाता है।

(ङ) और (च) नगर निगम दिल्ली से इस कालोनी में जल आपूर्ति की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।